

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक: 16 जुलाई, 2008

विषय:—मै0 पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को पंचकर्म व्यवस्था, औषधि उत्पादन, औषधि निर्माणशाला व प्रयोगशाला आदि की स्थापना हेतु जनपद हरिद्वार की तहसील रुड़की में कुल 50 है0 भूमि कय करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या— 1035/भूमि व्यवस्था-भू0क0-06 दिनांक 07 सितम्बर, 2006 तथा पत्र सं0- 334/भूमि व्यवस्था-भूमि कय-8 दिनांक 16 मई, 2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मै0 पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को आर्युवेद, पंचकर्म व्यवस्था, औषधि निर्माणशाला व प्रयोगशाला आदि हेतु उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 154(2) एवं उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(I) के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा अपने उपरोक्त पत्र दिनांक 07 सितम्बर, 2006 संस्तुत खसरा नम्बरान के अनुसार जनपद हरिद्वार के ग्राम औरंगाबाद, शिवदासपुर उर्फ तेलीवाला, शान्तरशाह तथा बहादुरपुर में कुल 50 है0 भूमि कय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:—

1— क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

2— क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3— क्रेता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था,

उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6- शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी एवं उक्त अवधि के भीतर प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करना होगा।

7- इकाई द्वारा फार्मसी को औषधि लाईसेंस निर्गत किये जाने के समय वातावरण प्रदूषण एवं संरक्षण सम्बन्धी लाभ का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8- प्रस्तावित इकाई में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को नियमित रूप से न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

9- इकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग औषधि निर्माणशाला व प्रयोगशाला तथा वैधिक अनुसंधानशाला तथा अन्य प्रस्तावित सुविधाओं की स्थापना के लिये ही किया जायेगा।

10- प्रस्तावित इकाईयों की स्थापना व संचालन के पूर्व नियमानुसार यथा आवश्यकता आयुष विभाग, चिकित्सा विभाग तथा उनके अधीन गठित संस्थाओं से अनापत्ति /स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

11- किसी भी दशा में क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य भूमि पर कब्जा न हो इसके लिए भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाये।

12- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

13- इकाई की स्थापना के पूर्व उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य वांछित विधिक एवं अन्य अनापत्तियां /अनुज्ञायें/प्रमाण पत्र आदि नियमानुसार प्राप्त कर लिये जायेंगे।

14- उक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 3- सचिव, चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- आचार्य बालकृष्ण, महामंत्री, पंतजलि योगपीठ ट्रस्ट, महर्षि दयानन्द ग्राम दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग, बहादुराबाद, हरिद्वार।
- 7- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सन्तोष/बडोनी)
अनुसचिव।